भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2626

(जिसका उत्तर मंगलवार, दिनांक 12 अगस्त, 2025 (21 श्रावण**,** 1947(शक) को दिया जाना है)

रूपये के मूल्य में उतार-चढ़ाव

2626. **श्री रामजी लाल सुमन:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रूपये के मूल्य में आए उतार–चढ़ाव का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) रूपये के निरंतर अवमूल्यन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और इन उपायों का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या रूपये के अवमूल्यन के कारण देश में आयातित वस्तुओं और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई अध्ययन किया गया है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये (आईएनआर) का वर्ष-वार मूल्य निम्नानुसार है:

तारीख	**अमेरिकी डॉलर/भारतीय रूपया विनिमय दर #**	**(+) मूल्यवृद्धि / (-) मूल्यह्रास %**
31-12-2019	71.38	-
31-12-2020	73.07	-2.31%
31-12-2021	74.34	-1.71%
30-12-2022	82.74	-10.15%
29-12-2023	83.21	-0.57%
31-12-2024	85.61	-2.80%
30-07-2025	87.43	-2.08%

 # ब्लूमबर्ग के अनुसार अमेरिकी डॉलर/भारतीय रूपया *समापन दर*

(ख) भारतीय रुपये (आईएनआर) का मूल्य बाज़ार द्वारा निर्धारित होता है, जिसका कोई लक्ष्य, विशिष्ट स्तर या बैंड नहीं होता। पिछले पाँच वर्षों में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा वित्तपोषण के स्रोतों में विविधता लाने और उनका विस्तार करने हेतु कई उपाय किए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

- मई 2025 में, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में उनके निवेश के लिए अल्पकालिक निवेश सीमा और संकेन्द्रित सीमा का अनुपालन करने की आवश्यकता को वापिस ले लिया गया।
- जनवरी 2025 से भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति, जो भारत में व्यावसायिक हित रखते हों, को सीमा पार भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत में किसी अधिकृत डीलर या भारत से बाहर उसकी शाखा के साथ विशेष अनिवासी रुपया खाता खोलने की अनुमति दी गई है।

- विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) (एफसीएनआर (बी)) जमा के लिए अधिकतम दर 6 दिसंबर, 2024 को बढ़ा दी गई, जिससे बैंकों को 31 मार्च, 2025 तक जुटाई गई ऐसी जमाओं पर उच्च ब्याज दर की पेशकश करने की अनुमति मिल गई।
- निर्धारित सीमा के उल्लंघन पर, एफपीआई द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को एफडीआई में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए एक कार्य संबंधी फ्रेमवर्क नवंबर 2024 में जारी किया गया।
- भारत में अधिकृत डीलरों को मई 2024 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन (डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए मार्जिन) विनियमों के संदर्भ में ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुमत डेरिवेटिव अनुबंध के लिए भारत में मार्जिन पोस्टिंग और कलेक्टिंग के उद्देश्य से भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों को भारतीय रुपये और/या विदेशी मुद्रा में ब्याज-सहित वाला खाता खोलने, रखने और बनाए रखने की अनुमति दी गई थी।
- वृद्धिशील एफसीएनआर **(बी)** और अनिवासी **(**बाह्य**)** रुपया **(**एनआरई**)** जमा देनदारियों को **4** नवंबर**, 2022** तक जुटाई गई जमाओं के लिए सीआरआर और एसएलआर के रखरखाव से छूट दी गई थी। नये एफसीएनआर **(बी)** और एनआरई जमाओं को **31** अक्टूबर**, 2022** तक ब्याज दरों **(**ब्याज दरें तुलनीय घरेलू रुपया सावधि जमाओं पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली दरों से अधिक नहीं होंगी**)** पर मौजूदा विनियमन से छूट दी गई थी। इसके अलावा**,** भारतीय ऋण लिखतों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण प्रवाह में एफपीआई निवेश से संबंधित विनियामक व्यवस्था को संशोधित किया गया है। बाह्य वाणिज्यिक उधार सीमा **(**स्वचालित माध्यम के अंतर्गत**)** को बढ़ाकर **1.5** बिलियन अमेरिकी डालर कर दिया गया**,** और **31** दिसंबर**, 2022** तक चुनिंदा मामलों में कुल लागत की सीमा को **100** बीपीएस तक बढ़ा दिया गया। प्राधिकृत व्यापारी (ए डी) श्रेणी-1 बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधारी हेतु यथाप्रयोज्य एंड-यूज प्रेस्क्रिप्शंस के लिए विदेशी मुद्रा में ऋण देने हेतु ओवरसीज विदेशी मुद्रा उधार का उपयोग कर सके।

(ग): मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की संभावना है, जिसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर, अवमूल्यन आयातित वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा सकता है। हालाँकि, घरेलू कीमतों पर विनिमय दर अवमूल्यन का समग्र प्रभाव अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों के घरेलू बाजार पर पड़ने वाले प्रभाव की सीमा पर निर्भर करता है। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था में आयात भी विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की मांग और आपूर्ति, व्यापार योग्य वस्तुओं का प्रकार (अर्थात आवश्यक या सुख-सुविधा की वस्तुएँ), माल ढुलाई लागत, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता आदि शामिल हैं। इस प्रकार, आयात लागत और इस प्रकार घरेलू मुद्रास्फीति तथा सामान्य रूप से उपभोक्ताओं पर विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को अलग नहीं किया जा सकता है। वाणिज्य विभाग समय-समय पर और विभिन्न स्तरों पर आयात के मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य हितधारकों की नियमित रूप से निगरानी करता रहा है तथा उन्हें संवेदनशील बनाता रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू आपूर्ति संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के अवसर तलाशना तथा आयात में वृद्धि की निगरानी करना शामिल है।

*****